

rafely, or along with those for regular students?

Dr. K. L. Shrimali: All these are matters of detail, which will have to be examined.

Shri Yallamanda Reddy: Are Government aware of the fact that in some of the States, the Government departments are not allowing their servants to attend evening classes?

Mr. Speaker: Now we cannot go into them. Each State cannot be taken up separately.

Shri Yallamanda Reddy: Some of the States are not allowing their employees to attend these classes. Has that fact been brought to the notice of Government and, if so, what action is proposed to be taken?

Dr. K. L. Shrimali: The hon. Member is asking questions which deal with State Governments. This is a matter for the State Governments to decide. As far as the Government of India is concerned this facility is provided and it is hoped it will be taken advantage of by those people who are in jobs. The correspondence courses are meant for them.

Mr. Speaker: He says some of the States refuse permission to their employees to attend evening classes.

Dr. K. L. Shrimali: In these matters each State Government will have to examine the situation. There may be certain situations in which they may refuse permission. I cannot give a general answer to this question. It is a matter for the State Governments.

उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा विवाद

+

*१५६६. { श्री सरजू पांडेय :
श्री मंत्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों के बीच सीमा विवाद, जिसमें प्रधान मंत्री

ने मध्यस्थता करना मंजूर कर लिया था, निबटाने में क्या कठिनाइयाँ हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार सरकार के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के हजारों खेतिहर मजदूरों को उन की मजदूरी के बदले में दिया गया धन इस वर्ष जव्त कर लिया है; और

(ग) क्या सरकार खेतिहर मजदूरों की कठिनाइयों को देखते हुए उन्हें अपनी मजदूरी के बदले में मिला हुआ अनाज अपने राज्य में ले जाने की सुविधाएं देने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बातार) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) पक्की सीमा निर्धारित करने के विषय में दोनों प्रदेशों की सरकारों के बीच मतभेद था । बिहार सरकार के विचार में नदी की धार की मालाना जांच के आधार पर सीमा निर्धारण का वर्तमान मिद्धांत ही ठीक था । उत्तर प्रदेश सरकार पक्की सीमा के पक्ष में थी ।

(ख) यह सच नहीं है कि बिहार सरकार के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के हजारों खेतिहर मजदूरों को उन की मजदूरी के बदले में दिया गया धन इस वर्ष जव्त कर लिया है, किन्तु कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के बलिया और गाजीपुर जिलों के २५ व्यक्तियों के खिलाफ ऐमैन्सिशनल कमीडिटीज ऐक्ट की धारा ७-८ के अधीन बिहार से उत्तर प्रदेश को धान ले जाने के जुर्म में मुकदमा चलाया गया था । उत्तर प्रदेश सरकार ने बिहार सरकार को लिखा है कि ये लोग खेतिहर मजदूर थे जो अपनी मजदूरी का धान ले जा रहे थे । बिहार सरकार मुकदमा वापस लेने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

(ग) बिहार खाद्यान्न (यातायात नियंत्रण) अधिनियम १९५७ की धारा (३) के अधीन अधिकृत प्रार्थी राज्य सरकार या उसके नियुक्त अधिकारी द्वारा जारी किये गये परमिट के अनुसार बिहार से बाहर कहीं भी प्रनाज ले जा सकते हैं ।

श्री सरजू पाण्डेय : मैं ने प्रश्न यह किया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के मीमा विवाद को तय करने के लिये प्रधान मंत्री ने मध्यस्था की है ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने दोनों राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों के साथ कोई वार्ता की है या नहीं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जी हाँ, प्रधान मंत्री जी की कुछ बातचीत हुई थी दोनों मुख्य मंत्रियों से और उन्होंने एक सज्जन को इस काम के लिये नियुक्त किया है कि वह मध्यस्था करें । आर्बिट्रेशन करें । वह इस काम को अपने हाथ में लेंगे ।

श्री सरजू पाण्डेय : जो विवरण दिया गया है, इसमें कहा गया है कि बलिया और गाजीपुर के कुल २५ खेत मजदूरों पर मुकदमे चलाये गये हैं । लेकिन मेरी सूचना इसमें भिन्न है । २५ से ज्यादा खेत मजदूरों के ऊपर अकेले बलिया से मुकदमे चले हैं और मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा है कि खेत मजदूरों से धान इत्यादि छीन करके उनको नंगे—

अध्यक्ष महोदय : अब आप सवाय करें ।

श्री सरजू पाण्डेय : मैं सवाल कर रहा हूँ । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय सरकार की तरफ से कोई ऐसा डायरेक्टिव दिया गया है बिहार सरकार को कि वह खेत मजदूरों की थोड़ी बहुत जांच करके उनको छोड़ दिया करें और वहाँ से धान, मजदूरी के रूप में जो वे लाते हैं, उसे ले आने दिया करे ? क्या ऐसा कोई डायरेक्टिव बिहार सरकार को दिया गया है या नहीं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : डायरेक्टिव देने की यह बात नहीं है । उनको यह सलाह दी गई है कि जहाँ तक हो सके मजदूर जो जाते हैं और उनको जो मजदूरी मिलती है प्रनाज के रूप में, उसको वहाँ से लाने में उनके रास्ते में कोई खाम दिक्कत पैदा न की जाये । लेकिन उनके कुछ कायदे कानून हैं जिसमें कुछ परमिट वर्गह की बात है । अगर वह चीज बहुत ज्यादा हो जाती है तब उसमें कुछ न कुछ नियमों का पालन करना जरूरी हो जाता है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं जानना चाहता हूँ कि यह जो भाग विवादास्पद है, इसमें कितने गांव और कितना भूभाग आ जाता है ? साथ ही जब तक इस विवाद का कोई हल न निकल आये तब तक के लिये इस क्षेत्र के निवासियों की समस्या का समाधान करने के लिये क्या यह उचित नहीं होगा कि केन्द्रीय सरकार अपनी देखरेख में उतने भूभाग को लें ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इसको माननीय सदस्य करीब करीब चीन और भारत के बार्डर का प्रश्न बना बैठे हैं । ऐसा कुछ नहीं है । इसे हल होना चाहिए, यह जरूरी है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरे पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है कि यह कितना भूभाग है और इसमें कितने गांव आते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : दूसरा सवाल आपने ऐसा कर दिया कि उन्होंने समझ लिया कि आपने पहले भाग के बारे में इतने गीगियस नहीं हैं ।

श्री राम सेवक यादव : जिनको प्रधान मंत्री जी ने इस काम के लिये नियुक्त किया है, उनका नाम क्या है और यह मीमा विवाद कितने दिन के अन्दर हल हो जायेगा ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : वह सज्जन श्री सी०एम० त्रिवेदी हैं जो प्लानिंग कमिशन के मੈम्बर हैं । अभी उन्होंने काम शुरू नहीं

किया है, लिहाजा यह कहना कि कब यह खत्म हो जायेगा, बहुत जल्दी है।

Shri Bhagwat Jha Azad: May I know whether this Arbitrator would hear the arguments on the Government basis of meeting the officials and Ministers or sit like a court and hear arguments from professional lawyers on behalf of the Government?

Shri Lal Bahadur Shastri: That is going into too much detail. He will perhaps decide for himself. I do not think he is going to function there as a law court, but he will certainly meet the officials, non-officials and he might also visit the spot and meet the people there.

Shri Basappa: May I know whether the mediation of the Prime Minister in such matters is confined only to U.P. and Bihar or whether it will also be extended to Mysore and Maharashtra?

Mr. Speaker: That is a different thing.

श्री भक्त दर्शन : क्या मध्यस्थ को नियुक्त करने से पहले बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की सरकारों की स्वीकृति ले ली गई है कि जो भी निर्णय दिया जाये, उसको वे मान लेंगे और उस पर अमल करेंगी ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें आर्बिट्रेशन की बात प्रधानमंत्री से कहनी ही नहीं चाहिये थी। जब यह कहा जाये कि आर्बिट्रेशन आप कर दें तो इसके जो फैसला होगा वह मान्य होगा।

Shri Jashvant Mehta: What are the points of reference to this Arbitrator?

Shri Lal Bahadur Shastri: It is a long one. The terms of reference will be:

(1) Whether the principle of fixed boundaries between the aforesaid districts should be accepted? If so,

whether they should be determined in the manner suggested at the 1952 Conference, or in a different way?

(2) If the principle of fixed boundaries is not advisable, what improvement should be made in the existing principle based on the deep-streams of the rivers Ganges and Ghagra?

(3) Whether, in the opinion of the Arbitrator, there can be any other solution to the question of the boundaries between the said districts? If so, what?

श्री त्यागी : इन दोनों गवर्नमेंट्स ने प्रधान मंत्री को मध्यस्थ स्वीकार किया था या उनके नामिनी को स्वीकार किया था ? प्रधान मंत्री जी ने क्या यह काम अपने ऊपर लिया था या यह कहा था कि वह कोई मुक्तपार नियुक्त कर दें अपनी तरफ से और उसको यह काम मौप देंगे ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जिम आदमी पर बहुत अधिक लोगों का विश्वास होता है वह अगर अपने काम में किसी की मदद ले ले तो वह भी विश्वास की बात है। 'उज़को पूरा विश्वास है और इसके वे पसन्द करते हैं। फैसला तो प्राइम मिनिस्टर का होगा लेकिन जिम की मदद वह लेना चाहते हैं, लेते हैं।

उत्तर प्रदेश में रासायनिक उर्वरक कारखाना

+

* १५६७ { श्री भक्त दर्शन :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिधवी :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उत्तर प्रदेश में मथुरा व आगरा के बीच एक रासायनिक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी लागत, उत्पादन-क्षमता, तथा उसकी स्थापना करने वाली फर्म का व्योरा बताने वाला एक विवरण